RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 11 OCTOBER TO 17 OCTOBER 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 4 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

जीएसटी परिषद ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कुछ उपायों को मंजूरी दी
Page 3

35 एकड़ जमीन, 75 साल पुराना इतिहास, 3 धर्मों का दावा
Page 4

सिट्रोएन ने भारत की पहली मेड-इन-इंडिया मिड-साइज़ एसयूवीऑल न्यू सी3 एयरक्रॉस एसयूवी का लॉन्च किया
Page 7

editoria!

लंबा युद्ध ठीक नहीं

इस्राइल पर शनिवार को हुए आतंकी हमले का पहला राउंड इस मायने में पूरा हुआ माना जा सकता है कि उसे अंजाम देने वाले संगठन हमास ने कहा है कि उसका जो मकसद था वह पूरा हो चुका है और अब वह युद्धविराम पर बातचीत के लिए तैयार है। इस कथित युद्धविराम प्रस्ताव का हालांकि कोई अर्थ नहीं था। स्वाभाविक ही इस्राइल ने उसे खारिज कर दिया। इस्राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में कहा कि युद्ध शुरू तो हमास ने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को फोन पर उनसे बात की और कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में उनके साथ है। बहरहाल, यहां दो सवाल उठते हैं। एक तो यह कि ऐसा क्या मकसद था इस आतंकी हमले का, जिसके बारे में हमास दावा कर रहा है कि वह पूरा हो गया। दूसरा यह कि लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के इस्राइल के संकल्प का आने वाले दिनों में बाकी पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब हो सकता है? जहां तक पहले सवाल की बात है तो अगर इस हमले को आम फलस्तीनियों की लड़ाई से जोड़कर देखा जाए तो भी एक आतंकी कार्रवाई फलस्तीनी मकसद को आगे बढ़ाने या उसके लिए दुनिया में सहानुभूति पैदा करने का काम नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा यह माना जा सकता है कि अपनी भीषणता और व्यापकता के कारण इस आतंकी हमले ने इस्राइली सुरक्षा तंत्र की साख पर बेइंतहा चोट की है और इस्राइली नागरिकों के दिलो-दिमाग पर इसका असर लंबे समय तक रहेगा। जहां तक इस्राइल की जवाबी कार्रवाई का सवाल है तो इतना तो तय है कि बात यहीं नहीं रुकेगी, जंग का दूसरा राउंड शायद पहले से ज्यादा भीषण होगा, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि नेतन्याहू सरकार इसे किस तरह से अंजाम देगी। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि गाजापट्टी उसके हमलों का निशाना बनेगी। गाजापट्टी में हमास का प्रभाव जरूर है, लेकिन वहां 23 लाख लोग रह रहे हैं जिनका एक बड़ा हिस्सा हमास की गतिविधियों और योजनाओं से अनजान होगा। ऐसे बेकसूर लोग जितनी बड़ी संख्या में इस्राइली कार्रवाई के शिकार होंगे, मानवाधिकार का सवाल उतने बड़े रूप में उभरेगा और फलस्तीनियों के लिए सहानुभूति भी बढ़ेगी। अभी लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला के कुछ हमले हुए हैं लेकिन लेबनान सरकार उस इलाके में शांति और स्थिरता बने रहने की इच्छा जताने तक सीमित है। ईरान और सऊदी अरब ने भी फलस्तीनियों के हक में शांति कायम करने की कोशिश की बात कही है। अगर बात बढ़ी और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमास के लिए समर्थन बढ़ा तो हालात बदतर ही होंगे। ऐसे भीषण हमले के बाद सुसंगत जवाबी कार्रवाई के लिए नेतन्याहू सरकार पर पड़ रहे दबाव को समझा जा सकता है। लेकिन सबकी बेहतरी इसी में है कि तनाव और संघर्ष को फैलने न दिया जाए।

ईरान से तेल की सप्लाई रोक देंगे..

इजराइल युद्ध में क्या इसी सोच के साथ कूद सकता है ईरान?

एजेंसी

ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश भी है और हमास का समर्थक भी। इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल और उसके बाजार ही पड़ेगा। इसकी एक झलक सोमवार को भी देखने को मिली, मध्य पूर्व में जारी तनाव के चलते, कच्चे तेल की कीमतें सोमवार को तेजी से बढ़ीं। पूरी दुनिया की एक तिहाई तेल सप्लाई इसी क्षेत्र से है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अब एक नया खतरा मंडराता दिखाई पड़ रहा है और वो है इजराइल हमास युद्ध । वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इजराइल हमास युद्ध के परिणाम को स्पष्ट होने में समय लग सकता है, लेकिन अगर ये लड़ाई मध्य पूर्व (Middle East) की बाकी हिस्से तक, खासकर ईरान तक फैल गई, तो ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश भी है और हमास का समर्थक भी। इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल और उसके बाजार ही पड़ेगा। इसकी एक झलक सोमवार को भी देखने को मिली, मध्य पूर्व में जारी तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें सोमवार को तेजी से बढ़ीं। पूरी दुनिया की एक तिहाई तेल सप्लाई इसी क्षेत्र से है।

रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा का मानना है कि अगर ये जंग ज्यादा बढ़ती है, तो इसमें सबसे पहला नुकसान तेल की सप्लाई का ही होगा। इस युद्ध का पूरे मिडल ईस्ट पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान का यही मकसद होगा कि हम रहें या न रहें, तेल की सप्लाई रोक देंगे। उसका सारा तेल ओरमुज की खाड़ी से होकर जाता है। मान लीजिए कि अगर ईरान वहां अपने ही तेल के दो टैंकर डुबा देगा, तो खाड़ी का रास्ता बंद हो जाएगा। क्योंकि उन टैंकर को वहां से हटाने की प्रक्रिया में इतना समय लग जाएगा कि तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी। बता दें कि गल्फ ऑफ ओरमुज, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये स्ट्रेट 55 से 95 km तक चौड़ा है और ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। सऊदी अरब, ईरान, UAE, कुवैत और इराक से निर्यात किए जाने वाला ज्यादातर कच्चा तेल को इसी रास्ते से दुनिया को भेजा जाता है।

आगा ने कहा, 'ऐसे में तेल की कीमत एक हफ्ता भी अगर ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है, तो मेरा मानना है कि ईस्टर्न यूरोप को जो 18-19 देश हैं, जो पहले से ही मंदी की कगार पर खड़े हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचेगी।' रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि ईरान को तो इस सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे तो पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। वहीं उन्होंने भारत को लेकर कहा कि जाहिर है, अगर तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा, तो भारत भी इसकी चपेट में आएगा। मध्य पूर्व, भारत का कच्चे तेल का पुराना सप्लायर रहा है। हालांकि, वित्त वर्ष 2023 के दौरान मिडल ईस्ट से प्रति दिन लगभग 12.1 लाख बैरल तेल का निर्यात घटा है।

एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म Vortexa की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में मध्य पूर्व की हिस्सेदारी 69 प्रतिशत थी, जो अप्रैल 2023 के दौरान घटकर 44 प्रतिशत हो गई। मतलब इसमें सीधे-सीधे 25 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। भारतीय रिफाइनरों ने यूक्रेन युद्ध के बाद सस्ते दर पर तेल की सप्लाई के लिए रूस का रुख किया है। जिस कारण मध्य पूर्वी देशों, जैसे इराक, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई।

व्यक्तिगत गारंटी पर लग सकता है 18% जीएसटी!

केंद्र इस संबंध में जल्द ही सर्कुलर जारी करेगा

नई दिल्ली। एजेंसी

कंपनी को मंजूर किए जाने वाले ऋण के संबंध में निदेशकों, प्रवर्तकों द्वारा बैंक को दी जाने वाली व्यक्तिगत गारंटी को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि केंद्र द्वारा इस संबंध में 'विशेष' मामलों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सर्कुलर जारी किए जाने की संभावना है, जिससे व्यक्तिगत गारंटी के मामले में 18 प्रतिशत की कर देनदारी को बढ़ावा मिल सकता है।

ये विशेष मामले ऐसे हालात से जुड़े हो सकते हैं जिनमें निदेशक (जिसने गारंटी दी थी) अब प्रबंधन से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसकी गारंटी जरूरी है और बरकरार है, क्योंकि नए प्रबंधन की गारंटी या तो उपलब्ध नहीं है या फिर अपर्याप्त है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इसके अलावा, जिन मामलों में प्रवर्तकों, मौजूदा निदेशकों, अन्य प्रबंधन कर्मियों और उधार लेने वाली कंपनियों के शेयरधारकों को किसी भी तरीके (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) से पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो, उनमें भी जीएसटी देनदारी बढ़ सकती है। जीएसटी परिषद ने शनिवार को हुई अपनी बैठक में निदेशकों, प्रवर्तकों द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत गारंटी पर कर लगाए जाने को लेकर चिंताओं को दूर किया। इस बैठक में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया कि उन लेनदेन पर कोई कर नहीं लगेगा, जिनमें संबंधित वैल्यू शून्य हो।

ईवाई इंडिया में टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा, 'व्यक्तिगत गारंटी के संदर्भ में स्पष्टता आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।'जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज का मतलब है कि कर आपूर्तिकर्ता के बजाय सीधे तौर पर प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाया जाएगा। इसके विपरीत,जीएसटी परिषद ने संबंधित व्यक्तियों (जिसमें होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनी सहायक इकाई को दी गई गारंटी भी शामिल है) को दी गई कॉरपोरेट गारंटी पर 18 प्रतिशत कर लगाने का भी निर्णय लिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कॉरपोरेट गारंटी के संबंध में निर्णय व्यावसायिक वास्तविकता के अनुरूप नहीं है।

कच्चा तेल 88 डॉलर प्रति बैरल के करीब, पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार-चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव 88 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 87 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक बुधवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये, डीजल 89.62 रुपये, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये, डीजल 94.27 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये, डीजल 92.76 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के पहले तीसरे दिन शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.25 डॉलर यानी 0.29 फीसदी लुढ़कर 87.90 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 0.16 डॉलर यानी 0.19 फीसदी की गिरावट के साथ 86.13 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

ग्राहकों के लिए अलर्ट

RBI ने जारी किया बयान, Account खोलने पर लगाई गई रोक

मुंबई। एजेंसी

बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के द्वारा ग्राहकों के लिए एक नया अपडेट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बैंक के मोबाइल ऐप 'बॉब वर्ल्ड' पर अभी फिलहाल नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति नहीं है। तत्कालीन प्रभाव से इस सेवा को रोक दिया गया है।

क्या है समस्या?

दरअसल, ऐप में ग्राहकों को जोड़ने से संबंधित प्रक्रिया में कुछ खामी पाई गई है जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। RBI ने इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव के साथ रोक दिया है। इसकी अनुमति अब तभी दी जाएगी जब सभी तरह की कमियों को दूर कर लिया जाएगा। RBI ने कहा है कि जांच के बाद पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही फिर से सेवाओं को शुरू किया जायेगा।

बैंक ने भी जारी किया बयान

इस मामले में बैंक के द्वारा भी बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि पहचान की गई कमियों को सुधारने की कोशिश की जा रही है और बाकी खामियों को भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बैंक ने कहा है कि बाकी सेवाएं बिना किसी परेशानी के जारी रहेंगी। नेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम आदि सेवा में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

गोल्ड लोन लिमिट से लेकर महंगाई और PM विश्वकर्मा योजना तक

जानिए आरबीआई गवर्नर की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली । एजेंसी

लोन की EMI चुकाने वालों और लोन लेने की सोच रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बैठक में रेपो रेट (Repo Rate) में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला हुआ है। इस तरह रेपो रेट 6.5 फीसदी पर बरकरार रहेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कांफ्रेंस कर बैठक में लिये गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। दास ने अपने स्टेटमेंट की शुरुआत कौटिल्य की बात के साथ की। उन्होंने कहा, 'कौटिल्य ने 2000 से भी अधिक दशक पहले अपनी अर्थशास्त्र में कहा था कि स्थिरता राज्य के लिए न सिर्फ समृद्धि को समानता से बांटने, बल्कि इसे संवर्धित करने के भी द्वार खोलती है।' आइए जानते हैं कि दास ने अपने स्टेटमेंट कौन-सी खास बातें कहीं।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत दुनिया का नया ग्रोथ इंजन बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है।

शक्तिकांत दास ने महंगाई को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उच्च महंगाई ग्रोथ के लिए एक बड़ा खतरा बनती है। उन्होंने कहा, 'ओवरऑल महंगाई परिदृश्य पर खरीफ की बुआई में गिरावट, लोअर रिजर्व ऑयल लेवल्स, ग्लोबल फूड और एनर्जी कीमतों में अनिश्चितताओं के बादल छाए हुए हैं।'

दास ने कहा कि सितंबर में भारत के सर्विस सेक्टर ने 13 साल की सबसे अधिक ग्रोथ रेट दर्ज की है। डिमांड में मजबूती से नए व्यापार अवसरों में पर्याप्त ग्रोथ के चलते ऐसा हुआ। ओवरऑल बिजनस सेंटीमेंट में सुधार से रोजगार की संख्या में भी इजाफा हुआ है।

वहीं, नए ऑर्डर्स में कमी के चलते सितंबर में मैन्यूफैक्चरिंग ऑपरेशंस 5 महीने के निम्न स्तर पर रहे। मैन्यूफैक्चिंग पीएमआई सितंबर में गिरकर 57.5 पर रही। यह अगस्त में 58.6 पर थी।

आरबीआई गवर्नर ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स के संबंध में गोल्ड लोन की लिमिट को 21 हजार से बढ़ाकर 41 हजार कर दिया है।

दास ने कहा कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम (इ्ध्ध्इ) को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लाभार्थियों को भी कवर करेगी।

दास ने कहा कि आरबीआई एमपीसी बैठक में चालू वित्त वर्ष की रियल जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान 6.5 फीसदी बताया गया। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान 6.6 फीसदी लगाया गया है।

महंगाई के पूर्वानुमान की बात करें, तो यह चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए 6.4 फीसदी, तीसरी तिमाही के लिए 5.6 फीसदी और चौथी तिमाही के लिए 5.2 फीसदी बताया गया है। वहीं, यह अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए 5.2 फीसदी है। आरबीई गवर्नर ने आगे कहा कि कोर इन्फ्लेशन में और गिरावट की आवश्कता है। उन्होंने कहा की महंगाई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल के चलते है।

आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि तेल के झटकों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए मौद्रिक नीति पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए।

दास ने कहा कि 29 सितंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 586.9 अरब डॉलर का था। साथ ही उन्होंने कहा कि ध्र्ध्ं को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है।

ग्रीन बॉन्ड जारी कर अर्बन लोकल बॉडीज जुटा रहीं मोटा पैसा

12 शहरों ने नगरपालिका बॉन्ड से 4,384 करोड़ जमा किये

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों (अर्बन लोकल बॉडी) को सलाह दी है कि सेवाओं को आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देना होगा। वित्तीय संसाधनों के लिए ग्रीन बॉन्ड जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। 12 शहरों ने नगरपालिका बॉन्ड के माध्यम से 4,384 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई है। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर और पुणे ने शहरी विकास को लेकर कई अहम प्रयोग किए हैं। छह शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच (आईजीओटी) कर्मयोगी यात्रा शुरू की है, जिसमें कुल 3,852 अधिकारियों का नामांकन हुआ है। सामूहिक रूप से 4,561 से अधिक कोर्स पूरे किए हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि लोगों को सरकारी सेवाओं का फायदा आसानी से पहुंचे।

ग्रीन बॉन्ड से जुटाया इन कार्यों के लिए पैसा

उ20 की बैठकों के दौरान में भी शहरी विकास के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर सौर ऊर्जा जैसे प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट टु एनर्जी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए फाइनैंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। ग्रीन कवर का दायरा बढ़ाने, वेस्ट टु एनर्जी प्रोजेक्ट, साफ पानी जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए शहरों को एक-दूसरे के साथ रणनीति साझा करनी होगी। हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश भर में सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए क्षमता निर्माण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना है। जो शहर अपने यहां नए प्रयोग कर रहे हैं, उनके बारे में दूसरे शहर भी देखें और अगर संभव हो तो उसको लागू करने के बारे में भी विचार किया जाए।

इंदौर बना पहला शहर

देश मे इंदौर पहला ऐसा शहर है, जहां पर ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इश्यू जारी किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाइमेट फाइनैंस के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ- साथ खुद के संसाधनों के विकास पर भी ध्यान देना होगा। शहर में ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और बिजली पर आने वाले खर्च को कम करने के लिए यह प्लान लागू किया गया था।

18 लाख करोड़ का निवेश

केंद्रीय आवास मंत्रालय के मुताबिक देश के शहरों और कस्बों के परिवर्तन में वर्ष 2014 से 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। 13वें वित्त आयोग ने वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-2015 की अवधि के बीच शहरी स्थानीय निकायों को 23,111 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। जबकि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-2026 के बीच यह राशि छह गुना बढ़कर 1,55,628 करोड़ रुपये हो गई।

अमीरों की लिस्ट, मुकेश अंबानी ने मारी बाजी, अडानी को पछाड़कर बने नंबर 1

मुंबई। एजेंसी

अडाणी समूह के प्रमुख गौतम अडाणी को पछाड़कर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। '360 वन वेल्थ हुरुन इंडिया' की भारतीय अमीरों की 2023 की लिस्ट के अनुसार, 66 वर्षीय अंबानी की संपत्तियां दो प्रतिशत बढ़कर 8.08 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं। अडाणी की संपत्ति 57 प्रतिशत घटकर 4.74 लाख करोड़ रुपये रह गई हैं। हुरुन के एमडी और चीफ रिसर्च एनालिस्ट अनस रहमान जुनैद ने अडाणी की संपत्ति में गिरावट के लिए जनवरी में प्रकाशित हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया है। अडाणी समूह ने इन आरोपों को खारिज किया था।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर साइरस एस पूनावाला तीसरे स्थान पर हैं। अमीरों की सूची में साइरस पूनावाला, शिव नादर के साथ ही कैवल्य वोहरा ने भी जगह बनाई है। बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन सूची से बाहर हो गए हैं। 61 वर्षीय अडाणी 2019 में छठे स्थान से बढ़कर 2023 में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी नेटवर्थ 4.74 लाख करोड़ रुपये है। उनकी संपत्ति में पांच गुना वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में अंबानी की संपत्ति 2.1 गुना बढ़ी है। साइरस पूनावाला और परिवार की संपत्ति बढ़कर तीन गुना हो गई है। टीका (वैक्सीन) बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला अब भी तीसरे सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। उनकी संपत्तियां 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2.78 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं। इस सूची में 138 शहरों के कुल 1,319 लोग शामिल हैं।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शिव नाडर की संपत्ति में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और वह 2.28 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियों के साथ चौथे स्थान पर बरकरार हैं। गोपीचंद हिंदुजा अब पांचवें स्थान हैं, जबकि छठे स्थान पर दिलीप सांघवी, सातवें स्थान पर लक्ष्मी निवास मित्तल, नौवें स्थान पर कुमार मंगलम बिड़ला और दसवें स्थान पर नीरज बजाज हैं। डी-मार्ट के राधाकिशन दमानी की कुल संपत्तियां 18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1.43 लाख करोड़ रुपये पर आ गईं। वह तीन पायदान फिसलकर अमीरों की सूची में आठवें स्थान पर आ गए हैं। जोहो की राधा वेम्बु ने फाल्गुनी नायर को पीछे छोड़ा है और वह सबसे अमीर भारतीय महिला बन गई हैं, जबकि जेप्टो के कैवल्य वोहरा इस सूची में सबसे कम उम्र की हैं।

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023

मुकेश अंबानी - 8.08 लाख करोड़ रुपये
गौतम अडाणी- 4.74 लाख करोड़ रुपये
साइरस पूनावाला -2.78 लाख करोड़ रुपये
शिव नादर - 2.28 लाख करोड़ रुपये
गोपीचंद हिंदुजा -1.76 लाख करोड़ रुपये

अब अरबपतियों की संख्या 259

हुरुन ने कहा कि भारत में पिछले साल हर तीन सप्ताह में दो नए अरबपति जुड़े और अब अरबपतियों की संख्या 259 हो गई है। यह 12 साल में 4.4 गुना वृद्धि है। पिछले साल 24 की तुलना में इस साल 51 लोगों की संपत्ति दोगुनी हुई है। भारत के अमीरों की सूची में 328 लोगों के साथ मुंबई शीर्ष पर रहा। इसके बाद नई दिल्ली से 199 और बेंगलुरु से 100 लोग इसमें शामिल हैं।

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आया 22 फीसदी का उछाल, सरकारी खजाने में हुआ इजाफा

नई दिल्ली। एजेंसी

चालू वित्त वर्ष में नौ अक्टूबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.82 प्रतिशत बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मुख्य रूप से कंपनियों और व्यक्तिगत करदाताओं की ओर से बेहतर योगदान से शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ा है। इसके साथ ही शुद्ध संग्रह 18.23 लाख करोड़ रुपये के पूरे साल के बजट अनुमान (बीई) का 52.5 प्रतिशत हो गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि नौ अक्टूबर, 2023 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के शुरुआती आंकड़ों में लगातार तेज वृद्धि देखने को मिली। बयान में कहा गया कि सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.07 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 17.95 प्रतिशत अधिक है। सकल राजस्व संग्रह में कॉरपोरेट आयकर (सीआईटी) और व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) की वृद्धि दर क्रमशः 7.30 प्रतिशत और 29.53 (सिर्फ पीआईटी) प्रतिशत रही। प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को मिलाकर पीआईटी की वृद्धि दर 29.08 प्रतिशत रही। रिफंड के समायोजन के बाद सीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 12.39 प्रतिशत है और पीआईटी संग्रह में यह वृद्धि 32.51 प्रतिशत (सिर्फ पीआईटी) और 31.85 प्रतिशत (एसटीटी सहित पीआईटी) है। बयान के मुताबिक, अप्रैल, 2023 से नौ अक्टूबर, 2023 तक 1.50 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है। आम बजट 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.23 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में जुटाए गए 16.61 लाख करोड़ रुपये से 9.75 प्रतिशत अधिक है।

जीएसटी परिषद ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कुछ उपायों को मंजूरी दी

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त विभाग संभालने वाले गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) के वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय और राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जीएसटी कर दरों में बदलाव, व्यापार सुविधा उपायों और अनुपालन को सुव्यवस्थित करने से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय और सिफारिशें शामिल हुईं।

वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों से संबंधित सिफारिशें

I. वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव

1) एचएस 1901 के तहत आने वाले 'पाउडर के रूप में मोटे अनाजों के आटे की खाद्य तैयारी, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70₹ मोटे अनाज शामिल हो' पर जीएसटी दरें निम्नलिखित तरीके से निर्धारित की गई हैं, जो अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी:

0% – यदि पूर्व-पैक और लेबल किए गए फॉर्म के अलावा किसी अन्य रूप में बेचा जाता है,

5% – यदि पूर्व-पैक और लेबल किए गए रूप में बेचा जाता है

2) एचएस 5605 के अंतर्गत आने वाले धातुकृत पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म से बने नकली ज़री धागे या धागे, 5% जीएसटी दर को आकर्षित करने वाले नकल वाले ज़री धागे या धागे की प्रविष्टि के तहत आते हैं। हालांकि, विपरीत होने की स्थिति में पॉलिएस्टर फिल्म (धातुकृत)/ प्लास्टिक फिल्म पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

3) यदि विदेश जाने वाले जहाज तटीय मार्ग पर परिवर्तित होते हैं तो उन्हें जहाज के मूल्य पर 5% आईजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। जीएसटी परिषद ने विदेशी ध्वज वाले विदेशी जहाज को तटीय मार्ग में परिवर्तित होने पर सशर्त आईजीएसटी छूट की सिफारिश की है, यदि यह छह महीने में विदेश जाने वाले जहाज में परिवर्तित हो जाता है।

II. वस्तुओं से संबंधित अन्य बदलाव

जीएसटी परिषद ने मानव उपभोग के लिए अल्कोहल शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से बाहर रखने की सिफारिश की है। मानव उपभोग के लिए अल्कोहल शराब के निर्माण में उपयोग हेतु ईएनए को जीएसटी के दायरे से बाहर करने के लिए विधि आयोग कानून में उपयुक्त संशोधन की जांच करेगा।

गुड़ पर जीएसटी 28% से घटाकर 5%। इस कदम से मिलों के पास नकदी बढ़ेगी और गन्ना किसानों को गन्ना बकाया का तेजी से भुगतान हो सकेगा। इससे पशु आहार के निर्माण की लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि इसके निर्माण में गुड़ भी एक सामग्री होती है।

औद्योगिक उपयोग के लिए संशोधित स्पिरिट को कवर करने के क्रम में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में 8 अंकों के स्तर पर एक अलग टैरिफ एचएस कोड बनाया गया है। 18₹ जीएसटी को आकर्षित करने वाले औद्योगिक उपयोग के लिए ईएनए से जुड़ी एक प्रविष्टि बनाने के लिए जीएसटी दर अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा।

III. सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव

अधिसूचना संख्या 12/2017-सीटीआर, दिनांक 28.06.2017 की क्रम संख्या 3 और 3ए की प्रविष्टियाँ; भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243जी और 243डब्ल्यू के तहत पंचायत/नगर पालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य के संबंध में केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों को शुद्ध और समग्र सेवाओं को छूट देती है। जीएसटी परिषद ने मौजूदा छूट प्रविष्टियों को बिना किसी बदलाव के बरकरार रखने की सिफारिश की है।

इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने सरकारी प्राधिकरणों को आपूर्ति की जाने वाली जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्लम सुधार और उन्नयन की सेवाओं को छूट देने की भी सिफारिश की है।

IV. सेवाओं से संबंधित अन्य बदलाव

यह स्पष्ट किया जाता है कि जौ का प्रसंस्करण माल्ट में करने से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर 'खाद्य और खाद्य उत्पादों से संबंधित जॉब वर्क' के समान ही 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है, न कि 18 प्रतिशत की दर से।

1 जनवरी 2022 से, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स (ईसीओ) के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली बस परिवहन सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने का दायित्व सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(5) के तहत ईसीओ पर रखा गया है। व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाला यह कदम उद्योग संघ के इस अभ्यावेदन पर उठाया गया है कि ईसीओ के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति करने वाले अधिकांश बस ऑपरेटरों के पास एक या दो बसें ही हैं और वे पंजीकरण लेने एवं जीएसटी अनुपालनों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि देशभर में खनिजों के खनन वाले क्षेत्रों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) सरकारी प्राधिकरण हैं और इसलिए वे जीएसटी से उसी प्रकार की छूट के पात्र हैं, जो किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण को उपलब्ध हैं।

भारतीय रेलवे द्वारा सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर लगाया जाएगा ताकि वे आईटीसी का लाभ उठा सकें। इससे भारतीय रेलवे की लागत कम हो जाएगी।

बी. व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले उपायः

परिषद ने वैसे कर योग्य व्यक्तियों के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 148 के तहत एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से एक माफी योजना प्रदान करने की सिफारिश की है, जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 या 74 के तहत 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले पारित मांग आदेश के खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा 107 के तहत अपील दायर नहीं कर सके या जिनकी उक्त आदेश के खिलाफ अपील केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उक्त अपील धारा 107 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी।

कंपनी को स्वीकृत की जा रही क्रेडिट सीमा/ऋण के विरुद्ध निदेशकों द्वारा बैंक को दी गई व्यक्तिगत गारंटी की करयोग्यता के संबंध में और होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी को प्रदान की गई।

यह स्पष्ट करते हुए एक सर्कुलर जारी करें कि जब कंपनी द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थानों को उनकी

ओर से व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में निदेशक को कोई भुगतान नहीं किया जाता है, तो उक्त लेनदेन/आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य शून्य माना जाएगा और इसलिए, सेवाओं की ऐसी आपूर्ति के संबंध में कोई कर देय नहीं होगा।

संबंधित पक्षों के बीच प्रदान की गई कॉरपोरेट गारंटी की आपूर्ति के कर योग्य मूल्य को ऐसी गारंटी की राशि का एक प्रतिशत या वास्तविक प्रतिफल, जो भी अधिक हो, प्रदान करने हेतु सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 28 में उप-नियम (2) को सम्मिलित करें।

एक वर्ष पूरा होने के बाद अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति की स्वतः बहाली का प्रावधानः परिषद ने सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 159 के उप-नियम (2) और फॉर्म जीएसटी डीआरसी-22 में संशोधन की सिफारिश की है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त आदेश की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद फॉर्म जीएसटी डीआरसी-22 में अनंतिम संलग्न संपत्ति का आदेश मान्य नहीं होगा। इससे आयुक्त के अलग से लिखित आदेश की ज़रूरत के बिना ही, एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अनंतिम रूप से संलग्न संपत्तियों की बहाली सुगम हो सकेगी।

कानून और प्रक्रियाओं से संबंधित अन्य उपायः

प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों को न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप करनाः परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 110 में संशोधन की सिफारिश की है, जिसमें व्यवस्था होगी किः

दस वर्षों से वकील व्यक्ति जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर न्यायाधिकरण, राज्य वैट न्यायाधिकरणों, या अन्य नामों से ज्ञात न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अप्रत्यक्ष कर कानूनों में मुकदमेबाजी का पर्याप्त अनुभव है, वह न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए;

अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः अधिकतम 70 वर्ष और 67 वर्ष की आयु तक होगा।

नई दिल्ली। एजेंसी

ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर बसी है। जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब इंसान बसते हैं। इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से सिर्फ 35 एकड़ जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है, जिसके लिए बरसों से जंग लड़ी जा रही है। जिस जंग में हजारों जानें जा चुकी हैं। सात अक्टूबर की रात जब दुनिया सो रही थी, ठीक उसी वक्त हमास ने इजरायल के अनगिनत ठिकानों पर अचानक रॉकेट से हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक हमास ने इस हमले में पांच हजार से लेकर सात हजार तक रॉकेट दागे। इस हमले में नौ सौ से ज्यादा इजरायली मारे गए। इसके जवाब में पलटकर इजरायल ने भी हमला किया। जिसमें तीन सौ से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 35 एकड़ जमीन के एक टुकड़े के लिए बरसों से इजरायल और फिलिस्तीन लड़ते आ रहे हैं।

35 एकड़ जमीन के लिए जंग

ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर बसी है। जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब इंसान बसते हैं। इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से सिर्फ 35 एकड़ जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है, जिसके लिए बरसों से जंग लड़ी जा रही है। जिस जंग में हजारों जानें जा चुकी हैं। लेकिन आज भी दुनिया की कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से इस 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। हमास का हमला और उसके जवाब में इजरायल की जोरदार बमबारी। जी हां, आप माने या ना मानें लेकिन सिर्फ 35 एकड़ जमीन के एक टुकड़े की वजह से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बरसों से ये जंग जारी है।

संयुक्त राष्ट्र के अधीन है पूरी जगह

इस जंग को समझने के लिए पहले 35 एकड़ इस जमीन की पूरी सच्चाई को समझना जरूरी है। यरुशलम में 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर एक ऐसी जगह है, जिसका ताल्लुक तीन-तीन धर्मों से है। इस जगह को यहूदी हर-हवाइयत या फिर टेंपल माउंट कहते हैं। जबकि मुस्लिम इसे हरम-अल-शरीफ बुलाते हैं। कभी इस जगह पर फिलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था। बाद में इजरायल ने इसे अपने कब्जे में लिया। लेकिन इसके बावजूद आज की सच्चाई ये है कि 35 एकड़ जमीन पर बसे टेंपल माउंट या हरम अल शरीफ ना तो इजरायल के कब्जे में है और ना ही फिलिस्तीन के बल्कि ये पूरी जगह संयुक्त राष्ट्र के अधीन है।

मुस्लिमों का दावा

मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम-अल-शरीफ उनके लिए तीसरी सबसे पाक जगह है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर हरम अल शरीफ पहुंचे थे। और यहीं से वो जन्नत गए। इसी मान्यता के मुताबिक तब येरुशलम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर एक मजसिद बनी थी। जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है। मान्यता है कि ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है, जहां यरुशलम पहुंचने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने पांव रखे थे। अल अक्सा मस्जिद के करीब ही एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है। इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। मुस्लिम मान्यता के मुताबिक ये वही जगह है, जहां से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। जाहिर है इसी वजह से अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र जगह है। इसीलिए वो इस जगह पर अपना दावा ठोकते हैं।

यहूदियों का दावा

यहूदियों की मान्यता है यरुशलम में 35 एकड़ की उसी जमीन पर उनका टेंपल माउंट है। यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी। जिससे आदम का जन्म हुआ था। यहूदियों की मान्यता है कि ये वही जगह है, जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। अब्राहम के दो बेटे थे। एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। अब्राहम ने खुदा की राय में इसहाक को कुर्बान करने का फैसला किया। लेकिन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक तभी फरिश्ते ने इसहाक की जगह एक भेड़ को रख दिया था। जिस जगह पर ये घटना हुई, उसका नाम टेंपल माउंट है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र है। बाद में इसहाक को एक बेटा हुआ। जिसका नाम जैकब था। जैकब का एक और नाम था इजरायल, इसहाक के बेटे इजरायल के बाद में 12 बेटे हुए। उनके नाम थे ट्वेल्व ट्राइब्स ऑफ इजरायल यहूदियों की मान्यता के मुताबिक, इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चल कर यहूदी देश बनाया। शुरुआत में उसका नाम लैंड ऑफ इजरायल रखा। 1948 में इजरायल की दावेदारी का आधार यही लैंड ऑफ इजरायल बना।

होली ऑफ होलीज का एक हिस्सा है वेस्टर्न वॉल

लैंड ऑफ इजरायल पर यहूदियों ने एक टेंपल बनाया। जिसका नाम फर्स्ट टेंपल था। इसे इजरायल के राजा किंग सोलोमन ने बनाया था। बाद में ये टेंपल दुश्मन देशों ने नष्ट कर दिया। कुछ सौ साल बाद यहूदियों ने उसी जगह फिर एक टेंपल बनाया। इसका नाम सेकंड टेंपल था। इस सेकंड टेंपल के अंदरूनी हिस्से को होली ऑफ होलीज़ कहा गया। यहूदियों के मुताबिक ये वो पाक जगह थी, जहां सिर्फ खास पुजारियों की छोड़ कर खुद यहूदियों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यही वजह है कि इस सेकंड टेंपल की होली ऑफ होलीज वाली जगह खुद यहूदियों ने भी नहीं देखी। लेकिन 1970 में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया। लेकिन इस टेंपल की एक दीवार बची रह गई। ये दीवार आज भी सलामत है। इसी दीवार को यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यहूदी इस वेस्टर्न वॉल को होली ऑफ होलीज के एक आहाते का हिस्सा मानते हैं। मगर चूंकि होली ऑफ होलीज के अंदर जाने की इजाजत खुद यहूदियों को भी नहीं थी, इसलिए वो पक्के तौर पर ये नहीं जानते कि वो अंदरुनी जगह असल में ठीक किस जगह पर हैं ? लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न वॉल की वजह से यहूदियों के लिए ये जगह बेहद पवित्र है।

ईसाइयों का दावा

ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ की जमीन से उपदेश दिया। इसी जमीन से वो सूली पर चढ़े। फिर दोबारा जी उठे। और अब जब वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे, तो भी इस जगह की एक अहम भूमिका होगी। जाहिर है ऐसे में ये जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है, जितनी मुस्लिमों या यहूदियों के लिए।

अब किसका कब्जा ?

अब सवाल ये है कि 35 एकड़ की जमीन का ये टुकड़ा जब तीन-तीन धर्मों के लिए इतना अहम है, तो फिर फिलहाल इस पर कब्जा किसका है? इन धार्मिक स्थलों की रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है? और इसके लिए खास तौर पर यहूदी और मुस्लिम आपस में लड़ते क्यों रहते हैं?

फिलिस्तीन और इजरायल की कहानी

1187 से पहले कुछ वक्त तक हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट पर ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था। लेकिन 1187 में हरम अल शरीफ पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसी के बाद से हरम अल शरीफ का पूरा प्रबंधन यानी कि देख रेख की जिम्मेदारी वक्फ यानी एक तरह से इस्लामिक ट्रस्ट को दे दी गई। तब से लेकर 1948 तक इस्लामिक ट्रस्ट ही हरम अल शरीफ का प्रबंधन देख रही थी। इस दौरान इस जगह पर गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं थी। 1948 से पहले हरम अल शरीफ फिलिस्तीन का एक हिस्सा हुआ करता था। हालांकि तब भी यहां कुछ यहूदी शरणार्थी के तौर पर रहा करते थे। लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन अंग्रेजों के अधीन था। 1948 में अंग्रेजों ने ही फिलिस्तीन के दो टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे 1947 में अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े किए थे। तब पूरे फिलिस्तीन की जमीन का 55 फीसदी टुकड़ा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45 फीसदी इजरायल के हिस्से में। इसी के बाद 14 मई 1948 को इजरायल ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया में पहली बार एक यहूदी देश का जन्म हुआ।

संयुक्त राष्ट्र ने निकाला ये रास्ता

मगर यरूशलम को लेकर लड़ाई अब भी जारी थी। क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे।। फिर धार्मिक लिहाज़ से भी यरूशलम ना सिर्फ मुस्लिम और यहूदी बल्कि ईसार्यो के लिए भी बेहद ख़ास था। तब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र बीच में आया और उसने एक तरह से फ़िलिस्तीन के एक और टुकड़े किए। अब यरूशलम का आठ फ़ीसदी हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया। जबकि 48 फीसदी जमीन का टुकड़ा फिलिस्तीन और 44 फीसदी टुकड़ा इजरायल के हिस्से में रह गया। येरुशलम का वो आठ फीसदी हिस्सा जो 35 एकड़ जमीन पर बसा है, वही हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट है। दरअसल, आजाद देश बनने के बाद इजरायल यरुशलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। जबकि फिलिस्तीन येरुशलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। इसको लेकर जब तब झड़प होतीं। इसी का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में ये फैसला हुआ कि 35 एकड़ जमीन के उस टुकड़े पर ना इजराइल का कब्जा रहेगा, ना फिलिस्तीन का, बल्कि वो सीधे संयुक्त राष्ट्र के अधीन रहेगा।

तीसरे देश के पास है प्रबंधन की जिम्मेदारी

पर इसके बावजूद एक मसला अब भी बचा हुआ था और वो ये कि हरम अल शरीफ या टेंपल माउंट के रख रखाव की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए? तो इसका भी हल निकाला गया। एक तीसरे देश जॉर्डन को हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही ये भी समझौता हुआ कि मुस्लिम यहूदियों को बाहर से उस टेंपल माउंट के दर्शन की इजाजत देंगे। हालांकि वो पूजा पाठ नहीं करेंगे। यही सिलसिला अब भी चला आ रहा है। लेकिन होता ये है कि दोनों ही तरफ के कट्टरपंथी लोग इस समझौते को नहीं मानते। इसीलिए जब कोई यहूदी टेंपल माउंट के दर्शन के लिए आता है, तो अंदर से उस पर पथराव किया जाता है। जवाब में इजरायल भी उन पर पथराव करता

फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा

इस समझौते के बावजूद 1956, 1967, 1973, 1982 में इज़रायल फिलिस्तीन लड़ते रहे और इज़रायल लगातार फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करता रहा। और फिर नौबत ये आ गई कि पहले 55 फ़ीसदी और फिर 48 फ़ीसदी से सिमटते हुए 22 फ़ीसदी और अब 12 फीसदी ज़मीन के टुकड़े पर ही फ़िलिस्तीन सिमट कर रह गया है। जबकि अधिकारिक रूप से यरूशलम को छोड़ कर इज़राइल लगभग बाक़ी के 80 फीसदी इलाके पर कब्ज़ा कर चुका है। ले देकर फ़िलिस्तीन के नाम पर अब दो ही इलाक़ा बचे हैं। एक गाजा और दूसरा वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक अमूमन शांत रहता है। जबकि गाजा गरम। क्योंकि गाजा पर एक तरह से हमास का कंट्रोल है और मौजूदा जंग इसी गाजा और इज़राइल के बीच है।

फिलिस्तीन के पास नहीं अपनी सेना

सारे रॉकेट और बम गाजा पट्टी से इजराइल पर गिराए जा रहे हैं और इजराइल भी इसी गाजा पर बम बरसा रहा है। नतीजा ये है कि पिछले तीन दिनों में अब तक दोनों तरफ से हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वैसे तो इज़रायल और फिलिस्तीन सालों से एक दूसरे से टकराते रहे हैं। दोनों मुल्कों की इस जंग में अब तक हज़ारों लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इज़ारयल बार-बार जिस फिलिस्तीन से लोहा लेता है, उस मुल्क यानी फिलिस्तीन के पास अपनी कोई सेना तक नहीं है?

इजरायल के पास बड़ी फौज

इज़रायल डिफेंस फॉर्सेस यानि घ्ब्ड्ड के पास एक लाख 70 हजार फौज के जवान और अधिकारी हैं जबकि उसके पास अस्थाई फौज के तौर पर तीस लाख से ज्यादा शहरी हमेशा फौज में अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं क्योंकि 90 लाख के देश में तीस लाख नागरिक ऐसे हैं जो फौज में सेवाएं देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसकी वजह ये है कि इज़रायल के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फौजी ट्रेनिंग जरूरी होती है।

हमास के पास 80 हजार लड़ाके

दूसरी तरफ फिलिस्तीन की हालत ये है कि वो खुद के हथियार के नाम पर कुछ रॉकेट्स ही बना पाता है, जिससे अक्सर इजराइल को निशाना बनाता है। हालांकि जानकारों की मानें तो इनमें से भी ज्यादातर रॉकेट वो या तो ईरान की मदद से बनाता है या फिर ईरान चोरी-छिपे इन रॉकेट्स की सप्लाई फिलिस्तीन को करता है। फिलिस्तीनियों के पास कोई स्थाई सेना तो नहीं है, लेकिन गाज़ा और वेस्ट बैंक में इज़राइलियों से लोहा लेने वाले हमास समेत कई लड़ाके गुट में और इनकी संख्या करीब 80 हज़ार के आसपास है।

1987 में हुआ था हमास का गठन

सवाल ये है कि अगर फिलिस्तीन के पास अपनी फ़ौज नहीं है, तो हमास फिलिस्तीन की ओर से क्यों लड़ता है? तो इसका जवाब हमास के वजूद में आने से है। फिलिस्तीनी इलाक़ों से इज़रायली फ़ौज को हटाने के इरादे से 1987 में इसका गठन किया गया था। और तब से लेकर अब तक हमास लगातार खुद को मुसलमानों का खैरख्वाह बताते हुए इज़ारयल से लोहा लेता रहा है। और तो और वो हमास इसरायल को मान्यता तक नहीं देता और पूरे फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहता है।

फिलिस्तीन की मदद करता है ईरान

लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये है कि जब हमास दुनिया के कई बड़े देशों की नज़र में एक आतंकवादी संगठन हैं, इसे किसी की मान्यता तक नहीं है, तो फिर इसे इज़रायल से लड़ने के लिए हथियार कहां से मिलता है? वो भी तब जब हमास के कब्जे वाली जगह गाज़ा पट्टी के एक तरफ खुद इज़रायल की सीमा है और दूसरी तरफ समंदर है। तो इसका जवाब है, गाजा पट्टी से सटा मिस्र का इलाका। दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन और इज़रायल के बीच जारी जंग में ईरान शुरू से फिलिस्तीन के साथ रहा है। और वही ईरान मिस्र के रास्ते गाज़ा पट्टी में फिलिस्तीनी गुट हमास को अपने रॉकेट भी मुहैया करवाता है।

फिलिस्तीन के पास कभी नहीं थी फौज

दरअसल, 150 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी क्योंकि तब वो ऑटोमन राज्य के तहत आता था। 100 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास फौज नहीं थी क्योंकि तब फिलिस्तीन का एक देश के तौर पर कोई वजूद नहीं था और वो ब्रिटिश हुकूत के अधीन था। 60 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास फौज नहीं थी क्योंकि तब वो जॉर्डन के हिस्से में आता था। 1988 में फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात ने पहली बार फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का नाम दिया, जिसे जॉर्डन और मिस्र ने अपनी रज़ामंदी दे दी। 1993 में इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच हुए ऑस्लो अकॉर्ड में इज़रायल ने फिलिस्तीन के फौज बनाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही फिलिस्तीन के पास अर्धसैनिक बल हैं तो जो वेस्ट बैंक इलाके में तैनात रहते हैं, लेकिन कोई स्थाई फ़ौज नहीं है। जबकि गाजा में सत्ता चलाने वाले हमास के पास लड़ाके हैं जो अक्सर इज़राइल को अपना निशाना बनाते रहते हैं।

इजरायल-हमास युद्ध का भारत पर भी पड़ने लगा असर

भारी नुकसान; नौकरियां जाने का भी डर

नई दिल्ली। एजेंसी

इजरायल-हमास के बीच चल रहे युद्ध से गुरुग्राम के उद्योगों पर असर पड़ रहा है। कई उद्योग के लिए माल नहीं मिल पा रहा है तो निर्यात में भी कमी आ गई है। इजरायल-हमास के बीच चल रहे युद्ध से गुरुग्राम के उद्योगों पर असर पड़ रहा है। यहां से गारमेंट, फूड और हस्तशिल्प उद्योगों से माल की सप्लाई होती है। उड़ानें रद्द होने से उद्यमियों को करोड़ों का माल भेजने की चिंता बढ़ गई है। इजरायल में युद्ध अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिले के उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे कई नए ऑर्डर भी रुक जाएंगे। युद्ध लंबा चला तो इन सेक्टर में काम करने वाले हजारों लोगों के रोजगार पर भी संकट आएगा।

गुरुग्राम जिले में 12 हजार उद्योग हैं। इसमें ऑटोमोबाइल के बाद ढाई हजार गारमेंट उद्योग है। इसके अलावा दो सौ फूड और हस्तशिल्प उद्योग है। इन तीनों उद्योगों से इजरायल को माल की सप्लाई होती है। ऑर्डर पर यहां से माल तैयार करके भेजे जाते है, लेकिन कई दिनों से इजरायल में चल रहे युद्ध से उद्यमियों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली से इजरायल की उड़ाने रद्द की दी गई। इससे तैयार माल को उद्यमी नहीं भेज पाएंगे। यहां से हर साल ढाई सौ करोड़ रुपये से अधिक कारोबार होता है। उद्योग विहार के गारमेंट उद्यमी संजय संन्याल ने कहा कि इजरायल में युद्ध जारी रहने से अब वहां से नए ऑर्डर मिलने बंद हो जाएंगे। साथ ही जो तैयार माल है उसे भी नहीं भेज पाएंगे।

खाद्य पदार्थों के खराब होने का सता रहा डर

मानेसर गारमेंट के उद्यमी सतीश चंद ने कहा कि चार प्रतिशत गारमेंट उद्यमी यहां से इजरायल में माल सप्लाई करते हैं। युद्ध होने से यह सप्लाई बंद हो जाएगी। इससे उद्यमियों को त्योहारी सीजन में नुकसान उठाना पड़ेगा। उद्योगों में तैयार माल भी भेज नहीं पाएंगे। सबसे अधिक फूड उद्योग पर पड़ेगा। क्योंकि यह ज्यादा दिनों तैयार माल को नहीं रख सकते हैं। गारमेंट उद्योग ही सौ करोड़ रुपये का कारोबार करता है। यह सब ठप होने से उद्योगों पर असर दिखाई देगा।

उद्यमियों को आर्थिक नुकसान होगा

प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन दीपक मैनी ने कहा कि इजरायल में चले रहे युद्ध से यहां से गारमेंट एक्सपोर्ट का कारोबार बड़े स्तर पर होता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों और हस्तशिल्प एक्सपोर्ट हो रही है। अब युद्ध के हालात बनने से इन सब पर सीधी असर पड़ेगा। वहीं, जिन उद्यमियों ने अपने पैसे उस देश में लगा रखे हैं, उनको सीधा तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। जिसका असर उद्यमियों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा।

टाटा और अडानी समेत इन कंपनियों का है इजरायल में निवेश, यहां देखिए पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

इजरायल और फिलीस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इसके साथ ही उन भारतीय कंपनियों की भी सांसें अटकी हुई हैं जिनका इजरायल में एक्सपोजर है। इनमें टीसीएस , इन्फोसिस , विप्रो , अडानी पोर्ट्स , एसबीआई , लार्सन एंड टुब्रो , भारत फोर्ज और सन फार्मा जैसी कंपनियां शामिल हैं। मंगलवार को इनमें से अधिकांश कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में कुछ शेयरों में गिरावट आई थी लेकिन दिन चढ़ने के सात वे पटरी पर लौट आए।

अडानी पोर्ट्स के शेयरों में तीन फीसदी से अधिक तेजी आई है। दोपहर बाद दो बजे कंपनी का शेयर 3.61 परसेंट की तेजी के साथ 818.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। अडानी पोर्ट्स ने पिछले साल इजरायल में हाइफा पोर्ट के प्राइवेटाइजेशन का टेंडर जीता था। हाइफा पोर्ट शिपिंग कंटेनरों में इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है। लेकिन कंपनी का कहना है कि उसके टोटल कार्गो वॉल्यूम में हाइफा की हिस्सेदारी महज तीन परसेंट है। टीसीएस के शेयरों में मामूली गिरावट दिख रही है जबकि विप्रो के शेयरों में तेजी आई है। विप्रो का कहना है कि उसके इजरायल में 80 कर्मचारी हैं और कंपनी ने सभी को घर से काम करने को कहा है।

शेयरों का हाल

इस बीच सन फार्मास्यूटिकल के शेयर में शुरुआत में गिरावट आई लेकिन जल्दी ही यह गिरावट से उबर गया। दोपहर बाद दो बजे यह 0.14 परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। सन फार्मा की इजरायली कंपनी तारो फार्मास्यूटिकल में मैज्योरिटी हिस्सेदारी है। इन्फोसिस का शेयर भी 1.1 फीसदी की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एसबीआई के शेयरों में 1.54 फीसदी, लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में 0.32 फीसदी और भारत फोर्ज के शेयरों में 2.57 फीसदी तेजी आई है। सुबह के कारोबार में निफ्टी और सेंसेक्स में करीब आधे परसेंट की तेजी देखने को मिली। जानकारों का कहना है कि इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग से भारतीय बाजार पर कोई बड़ा असर होने की आशंका नहीं है।

इजरायल हमले के बीच एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए सभी उड़ानों को किया रद्द

नई दिल्ली। एजेंसी

इजरायल पर हमास आतंकियों ने हमला बोल दिया है। इजरायल पर हुए इस हमले में बडी संख्या में लोगों की मौत की खबर आ रही है। इजरायल ने इस हमले को युद्ध बताते हुए कहा है कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजरायल में युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। इस हमले के बाद भारत सरकार की ओर से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वहीं एयर इंडिया ने इजरायल के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। हमास आतंकियों के इजरायल पर किए हमले में अब तक 900 के करीब इजरायली मारे गए है तो वहीं 600 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। वहां के हालात को देखने के बाद एयर इंडिया ने ये फैसला लिया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एयर इंडिया ने 7 अक्टूबर को दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली और तेल अवीव से दिल्ली की वापसी करने वाली AI140 उड़ान को रद्द करने का फैसला लिया है। एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों और हमारे क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। एयर इंडिया के फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद यात्रियों को होने वाली असुविधा को लेकर कहा है कि उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है।

रुपया सात पैसे की बढ़त के साथ 83.18 प्रति डॉलर पर

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और अमेरिकी मुद्रा के कमजोर रुख के बीच बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सात पैसे की बढ़त के साथ 83.18 (अस्थायी) पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के दबाव का असर भारतीय मुद्रा पर पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में रुपया 83.20 प्रति डॉलर पर खुला। डॉलर के मुकाबले रुपया 83.15 से 83.24 के दायरे में करोबार करने के बाद अंत में 83.18 (अस्थायी) पर बंद हुआ। इस तरह रुपये ने पिछले बंद भाव के मुकाबले सात पैसे की बढ़त दर्ज की। मंगलवार को रुपया 83.25 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.09 प्रतिशत घटकर 105.73 पर रहा। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ 87.08 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स बुधवार को 393.69 अंक की बढ़त के साथ 66,473.05 अंक पर, निफ्टी 121.50 अंक के लाभ से 19,811.35 अंक पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 1,005.49 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

शुरू होने वाली है नवरात्रि

घर से बाहर निकाल दें ये 5 वस्तुएं, नहीं तो मां दुर्गा हो जाएंगी नाराज!

इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है और नवमी तिथि तक होती है. दशमी के दिन विजयादशमी मनाई जाती है, जिसे दशहरा भी कहते हैं. इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर को महानवमी तक है, उसके बाद 24 अक्टूबर को दशहरा है. नवरात्रि पर हर हिंदू ?परिवार अपने घर में मां दुर्गा के आगमन की तैयारी करता है ताकि मातारानी का आशीर्वाद उसके परिवार पर हो और उनकी उन्नति हो. हालांकि नवरात्रि पूर्व आपको अपने घर से कुछ वस्तुओं को निकाल देना चाहिए, जिससे नकारात्मकता फैलती है. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे मातारानी नाराज हो सकती हैं या उनका आगमन आपके घर न हो।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

इन वस्तुओं को घर से कर दें बाहर

1. खंडित मूर्तियां और फोटो

यदि आपके घर में देवी और देवताओं की खंडित मूर्तियां या फोटो हैं, ऐसी मूर्तियां हैं जो कांतिहीन हो चुकी हैं तो उनको तत्काल घर से बाहर निकाल दें. उनको किसी पीपल या वट वृक्ष के नीचे रख दें या फिर उनको किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें. ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से दोष लगता है और घर में रखने से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है.

2. टूटे बर्तन और उपकरण

आपके घर में अनुपयोगी गैस चूल्हा, बेकार बिजली के उपकरण पड़े हों या किचन में टूटे-फूटे बर्तन हों तो उनको घर से बाहर कर देना चाहिए. टूटे-फूटे बर्तन रखने से दरिद्रता आती है और खराब उपकरण घर में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करते हैं. इससे परिवार के लोगों के विचारों और सेहत पर बुरा असर हो सकता है.

3. रद्दी और कूड़ा

यदि आपके घर में कागज की रद्दी, फटी-पुरानी पुस्तकें, अखबार और अन्य कूड़ा आदि पड़े हैं तो उनको भी घर से बाहर कर दें. घर की अच्छे से साफ-सफाई करें. उसके बाद नवरात्रि के लिए तैयारी करें. मां दुर्गा के स्वागत के लिए घर को सजाएं. गंदे घरों में देवी और देवताओं का वास नहीं होता है.

4. पूजा घर की अशुद्ध सामग्री

पूजा घर हमारे आवास का अहम हिस्सा है. पूजा घर को साफ सुथरा रखना जरूरी है. इसके लिए आप वहां पर पड़े पुराने कलावे, अशुद्ध फूल, खराब नारियल, टूटा हुआ माला आदि जो भी हों, उनको हटा दें. इन सब के कारण दोष उत्पन्न होता है. पूजा में बासी फूल का उपयोग भी वर्जित है. कई बार हम पिछले व्रत और त्योहारों की सामग्री को सही से नहीं रखते और वे धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको भी हटा देना जरूरी है.

5. तामसिक वस्तुएं

नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित हैं. इसमें पवित्रता और व्रत के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस वजह से नवरात्रि में तामसिक वस्तुओं का उपयोग पूर्णतया वर्जित है. तामसिक वस्तुओं में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि शामिल हैं.

शनिश्चरी अमावस्याः किस्मत नहीं दे रही साथ, मेहनत के बाद भी हाथ नहीं आ रहा पैसा

जरूर करें 5 उपाय, प्रसन्न हो जाएंगे न्याय के देवता

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

शनि अमावस्या इसबार 14 अक्टूबर दिन शनिवार को है और यह साल का अंतिम शनिश्चरी अमावस्या है. अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है. इस दिन किस्मत को बदलने वाले कई शुभ योग भी बन रहे हैं. ऐसे में लोगों को शनिदेव से जुड़े कुछ सरल उपायों को फॉलो करना चाहिए. इन उपायों को करने से शनिदेव की कृपा होती है और दुखों का नाश होता है. इसके साथ ही शनिदोष से भी मुक्ति मिलती है.

शास्त्रों के अनुसार, सूर्य पुत्र शनिदेव यमराज के भ्राता और भद्रा के भाई हैं. वह न्याय के देवता हैं और वह लोगों के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं. इसीलिए शनि अमावस्या के दिन का विशेष महत्व होता है. यदि किसी इंसान की किस्मत साथ नहीं दे रही है या मेहनत करने के बाद भी हाथ में पैसा नहीं रुकता है. इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में शनि दोष है. इससे मुक्ति पाने के लिए न्याय के देवता को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है. हालांकि, शनिश्चरी अमावस्या पर कुछ उपाय के करने से शनिदेव की कृपा आप पर होगी और किस्मत का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा. इसके अलावा जीवन में आर्थिक संपन्नता भी बनी रहेगी.

काली गाय की पूजा और परिक्रमा करें

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, शनिश्चरी अमावस्या के दिन काली गाय की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. हालांकि, ये ध्यान रखें कि काली गाय पर कोई कोई दूसरा निशान ना हो. पूजा के लिए काली गाय को 8 बूंदी के लड्डू खिलाएं. इसके बाद उसकी 7 बार परिक्रमा करें. जब परिक्रमा पूर्ण हो जाए तब गाय की पूंछ से अपने सिर पर 8 बार झाड़ा लगाएं. इस उपाय को करने से शनिदेव की कृपा होती है. साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट मिटते हैं.

नारियल और काले-सफेद तिल का टोटका करें

शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिश्चरी अमावस्या पर नारियल से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए. ऐसा करने से शनिदोष से मुक्ति मिलती है. इस टोटको करने के लिए आप पानी वाले 11 नारियल, 400-400 ग्राम काले-सफेद तिल्ल, नौ कीलें, आठ मुट्ठी जौ, आठ मुट्ठी काले चने और आठ मुट्ठी कोयला लें. इसके बाद इन सभी चीजों को काले कपड़े में बांधकर सायंकाल में नदी के किनारे पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने ऊपर से 7 बार सिर से लेकर पैर तक घुमा लें. फिर एक-एक करके प्रवाहित कर दें. आप इसको शनिदेव के मंदिर में भी रख सकते हैं.

काली उड़द की दाल सिर के पास रखकर सोएं

शनि अमावस्या पर काली उड़द की दाल का उपाय करने से जीवन में समृद्धि आती है. इस उपाय को एक दिन पहले यानी शुक्रवार की रात को करना है. इस दिन सवा पाव काली उड़द की दाल को काले कपड़े में बांधकर सिर के पास रखकर सोना है. हालांकि, यह ध्यान रखें कि उस दिन अपने पास किसी को ना सोए. इसके बाद शनिवार को शनि मंदिर में उस पोटली को रख दें. इसके बाद सायंकाल के समय काले सुरमे की शीशी को सिर से लेकर पैर तक 9 बार किसी से उतरवा लें और फिर उसको किसी सुनसान जगह पर जमीन में दबा दें. ऐसा करने से शनि ढैय्या व साढ़ेसाती का अशुभ प्रभाव कम होता है.

नवग्रह मंदिर में शनिदेव की पूजा-आराधना करें

शनिदेव को प्रसन्न करके उनके कृपा पाने के लिए शनि अमावस्या पर कुछ उपाय बेहद जरूरी है. इसके लिए शनि अमावस्या पर नवग्रह मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा-आराधना करनी होगी. पूजा-अर्चना करने के बाद शनि चालीसा या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनि मंत्रों का भी जप करें. इसके तत्पश्चात शनिदेव पर काले तिल, तेल और नीले रंग के फूल अर्पित करें. ऐसा करने से जीवन में उन्नति होगी, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा. साथ ही शनिदोष से मुक्ति मिलेगी.

शनि अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करें

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, शनि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है. इस उपाय को करने के लिए इस दिन सुबह पीपल की जड़ में दूध और जल अर्पित करें. इसके बाद पीपल के 5 पत्तों को लेकर उसमें पांच मिठाई रख देंगे और फिर घी का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करेंगे. इसके अलावा, इस दिन का पीपल का पेड़ भी लगाया जा सकता है. इसके लिए आप रविवार का दिन छोड़कर हर रोज जल दें. ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे सोई किस्मत जाग जाएगी.

सर्व पितृ अमावस्याः पितृ दोष से चाहते हैं मुक्ति?

काले तिल से जुड़े 4 उपाय करें फॉलो आशीर्वाद देने चले आएंगे पितर

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने और उनकी तृप्ति के लिए अच्छा मौका होता है. पितर आपके नाराज हैं तो उनको खुश करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करना बेहद जरूरी होता है. नाराज पितरों के श्राप से पितृ दोष लगता है, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन अशांत हो जाता है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, पितरों की नाराजगी केवल परिवार पर ही नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों तक नुकसान पहुंचाती है. घर में कलह होती है, धन हानि होती है, तरक्की रुक जाती है और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं. वहीं, यदि पूर्वज प्रसन्न हो जाएं तो कई पीढ़ियां तर जाती हैं और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है. ऐसे में यदि आप भी पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं तो सर्व पितृ अमावस्या पर काले तिल का उपाय जरूर करना चाहिए.

सर्व पितृ अमावस्या पर काले तिल के 4 आसान उपाय

यम होंगे प्रसन्नः सर्व पितृ अमावस्या पर नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं. इनमें काले तिल से जुड़े उपाय चमत्कारी होते हैं. ऐसे में पितृ पक्ष के समय में जब आप पितरों को तर्पण दें तो जल में काला तिल जरूर मिला लें. ऐसा करने से पितर खुश होते हैं, क्योंकि काला तिल यमराज को प्रिय है. जो पितर यम लोक में कष्ट भोगते हैं, उनको इससे राहत मिलती है. इससे खुश होकर पितर आशीर्वाद देते हैं और दोषों से मुक्त करते हैं.

सूर्य देव होंगे खुशः पितृ पक्ष में सूर्य देव अर्ध्य देना बेहद जरूरी होता है. ऐसा करने से कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है. दोषों से मुक्ति पाने के लिए सर्व पितृ अमावस्या बेहद खास होती है. दरअसल, अर्यमा को पितरों का देव कहा जाता है. ऐसे में अर्यमा की पूजा करके उनको काला तिल अर्पित करें. ऐसा करने से पितर खुश होते हैं. वंश को देव अर्यमा और पितर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

भगवान विष्णु होंगे प्रसन्नः सर्व पितृ अमावस्या पर इंदिरा एकादशी व्रत पितरों के लिए खास माना जाता है. इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा होती है. ऐसे में श्रीहरि को काला तिल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं. दरअसल, तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है. इसलिए तिल अर्पण के बाद विधिपूर्वक व्रत करें. इससे भगवान विष्णु और पितर दोनों ही प्रसन्न होंगे. साथ ही पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है.

त्रिग्रही दोष होंगे शांतः पितृ पक्ष के समय आप पूजा में काले तिल का उपयोग करते हैं तो कुंडली से त्रिग्रही दोष शांत होते हैं. ऐसे में यदि आप सर्व पितृ अमावस्या पर काले तिल का उपाय करेंगे तो राहु, केतु और शनि ये तीनों ग्रह शांत होंगे. इसके अलावा इनका जीवन पर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा.

शक्ति पम्पस् को मिला पीएम-कुसुम-स्कीम-कम्पोनेन्ट -सी का पहला कमर्शियल ऑर्डर

आईपीटी नेटवर्क

पीथमपुर। रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्र में प्रमुख कंपनी शक्ति पंप्स को अजमेर विद्युत वितरण निगम के द्वारा पीएम-कुसुम स्कीम कम्पोनेन्ट-सी के तहत अपना पहला 149.7 करोड़ रुपये का कमर्शियल ऑर्डर प्राप्त हुआ। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि सौलर एनर्जी के उपयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो ऊर्जा और कृषि पद्धतियों को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कार्य करती है। इस परियोजना में अकुशल विद्युत पंपों को बीएलडीसी सोलर पंपसेटों से बदला जाएगा जहां पंपसेट सौलर एनर्जी के माध्यम से उत्पन्न बिजली पर चलेंगें और शेष बिजली को ग्रिड में भेजा जा सकेगा, शेष बची हुई बिजली को डिस्कॉम को बिक्री करने से किसानों को कमाई का अवसर भी प्राप्त होगा। शक्ति पंप्स के चेयरमैन श्री दिनेश पाटीदार जी ने सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा, ''यह परिवर्तनकारी प्रयास 'अन्नदाता' को 'ऊर्जा दाता' में बदल देगा। पम्पसेट की कास्ट 10 लाख रुपये है और प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये की बिजली बचाकर डिस्कॉम अपने पंपसेट की कास्ट को 5 साल में रिकवर कर पाएगा और साथ ही यह किसानों को कई तरह से सहायता प्रदान करेगा जैसे- 2 लाख तक की सालाना बिजली बिल की बचत और डिस्कॉम को शेष बिजली बेचकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष और पांच वर्षों में 2.5 लाख रुपये तक कमाने का अवसर प्राप्त होगा। यह स्कीम किसानों की सिंचाई क्षमताओं को बढ़ाता है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करता है, जिससे पूरे देश में किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त होगी।'' (यह सेविंग कैल्कुलेशन कंपनी के इंटर्नल डिपार्टमेन्ट ने 10 एचपी के पम्पसेट पर की गई है) इस योजना से डिस्कॉम को किसानों से 3 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली खरीदने और इसे 6 रुपये प्रति यूनिट पर बेचने का अवसर प्राप्त होगा। जिससे डिस्कॉम पर टैरिफ सब्सिडी का बोझ कम होगा। यह सिस्टम स्थानीय रूप से इंस्टॉल किया जाएगा और डिस्कॉम के वितरण नेटवर्क से जुड़ा होगा। जिसके कारण ग्रिड के संचालन में आसानी होगी एवं टी एंड डी लॉस में कमी आएगी। ऊर्जा दक्षता और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने मे और डिस्कॉम को अपने आरपीओ दायित्व को पूरा करने और सोलर को जोड़कर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी। यह स्कीम 2030 तक नॉन-फॉसिल फ्यूल (Non-Fossil Fuel)के सोर्सों से 40% तक की इंस्टॉल कैपेसिटी को पूर्ण करने में भारत की मदद करेगी। सौलर पंपिंग सिस्टम से जुड़ा ग्रिड एक साथ ऑपरेट करने में सक्षम होगा यानी एक ही समय में पंप का संचालन और ग्रिड को ऊर्जा एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी, इससे ग्रिड में अधिक ऊर्जा भेजी जा सकेगी जिससे किसानों को अधिक आय प्राप्त होगी साथ ही पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा। यह माइक्रो एरिगेशन, (Per drop more crop),के माध्यम से किसानों और पूरे देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, जिससे अधिक फसल, अच्छी उपज, गुणवत्ता और कृषि उपज की अच्छी कीमत प्राप्त होगी। शक्ति पंप्स को इस परिवर्तनकारी पहल में भाग लेने पर गर्व है और वह भारत के भविष्य में योगदान देने के लिए तत्पर है।

हीरो मोटोकॉर्प को करिज़्मा एक्सएमआर के लिए 13,688 बुकिंग मिली

डिलीवरी इस महीने से शुरू हो जाएगी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

दुनिया में मोटरसाइकिल और स्कूटर की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को हाल ही में लॉन्च की गई प्रमुख मोटरसाइकिल करिज़्मा एक्सएमआर के लिए 13,688 बुकिंग्स प्राप्त हुई हैं। इससे पहले भी लॉन्च किए गए कंपनी के प्रीमियम प्रॉडक्ट्स को उपभोक्ताओं का जबर्दस्त रेस्पॉन्स मिला है।

हीरो मोटोकॉर्प की डीलरशिप्स पर पहले ही करिज़्मा एक्सएमआर का डिस्पैच शुरू किया जा चुका है। उपभोक्ताओं को इस मोटरसाइकिल की डिलिवरी इस महीने त्योहारी सीजन से मिलनी शुरू हो जाएगी। हीरो करिज़्मा एक्सएमआर को 1,72,900 रुपये के शुरुआती दाम पर लॉन्च किया गया था। शुरुआती चरण में उपभोक्ताओं के लिए इस बाइक की बुकिंग की शुरुआत 29 अगस्त 2023 से हुई थी और 30 सितंबर 2023 को इसकी बुकिंग बंद की गई थी। नई करिज़्मा एक्सएमआर अब 1,79,900 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) में उपलब्ध होगी। कंपनी जल्द ही नई बुकिंग विंडो खोलने की घोषणा करेगी।

हीरो मोटोकॉर्प में इंडिया बिजनेस यूनिट के चीफ बिजनेस ऑफीसर श्री रंजीवजीत सिंह ने कहा, 'हीरो करिज़्मा एक्सएमआर को मिले जबर्दस्त रिस्पॉन्स से हम काफी उत्साहित और उपभोक्ताओं के आभारी हैं। इस प्रमुख मोटरसाइकिल के प्रति उपभोक्ताओं के उत्साह और इतनी बड़ी संख्या में हुई बुकिंग से उपभोक्ताओं के कंपनी में अटूट विश्वास का पता चलता है। लीजेंड मोटरसाइकिल ने वास्तव में अपने आधुनिक, कंटेम्परेरी अवतार में वापसी की है और उपभोक्ता इसे पसंद कर रहे हैं। हम करिज़्मा के हर मालिक को असाधारण रूप से प्रीमियम राइडिंग का अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। हमें भरोसा है कि इससे उपभोक्ताओं के लिए त्योहार की खुशियां और बढ़ जाएंगी।' नई करिज़्मा एक्सएमआर अपनी श्रेणी की सबसे ताकतवर मोटरसाइकिल है, जो सबसे ज्यादा टॉर्क पैदा करती है। मोटरसाइकिल 210 सीसी के लिक्विड कूल्ड डीओएचसी इंजन और 6-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस है। इसमें स्लिप और असिस्ट क्लच और ड्यूल चैनल एबीएस की खूबियां भी हैं।

सिट्रोएन ने भारत की पहली मेड-इन-इंडिया मिड-साइज़ एसयूवी

ऑल न्यू सी3 एयरक्रॉस एसयूवी का लॉन्च किया

चेन्नई। एजेंसी

फ्रेंच कार निर्माता, सिट्रोएन की नवीनतम पेशकश, नई सी3 एयरक्रॉस एसयूवी, अब 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम नई दिल्ली) के विशेष इंट्रोडक्टरी मूल्य में उपलब्ध है। इस नई एसयूवी में 90 प्रतिशत से ज़्यादा लोकलाईज़ेशन कर दिया गया है, और यह भारतीय ग्राहकों की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत में डिज़ाइन की गई है।

स्टेलैंटिस इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, रोलैंड बूचारा ने कहा, 'हमें प्रबुद्ध ग्राहकों के लिए भारत में डिज़ाइन, डेवलप, और निर्मित की गई बहुप्रतीक्षित नई सी3 एयरक्रॉस एसयूवी लॉन्च करने की खुशी है। इस एसयूवी को सिट्रोएन के डीएनए की मुख्य विशेषताओं – कम्फर्ट और इनोवेशन के साथ बनाया गया है। सितंबर में इसकी बुकिंग शुरू होने के बाद इसे पूरे देश में बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है। त्योहारों पर मांग को पूरा करने के लिए हम अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हमारे शोरूम्स एवं वर्कशॉप्स का लगातार बढ़ता और विकसित होता हुआ नेटवर्क सी3 एयरक्रॉस एसयूवी की आपूर्ति करने के लिए तैयार है, जिसमें श्रेणी की अग्रणी विशेषताएं, आकर्षक स्टाइलिंग और अतुलनीय उपयोगिता है।'

आसान ओनरशिप

31 अक्टूबर 2023 तक की डिलीवरी के लिए अभी खरीदें 2024 में भुगतान करें। सिट्रोएन फाइनेंस अपने फाइनेंस पार्टनर के साथ मिलकर एक अद्वितीय लोन ऑफर दे रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राहक 31 अक्टूबर 2023 तक कार खरीद सकते हैं, जिसकी ईएमआई 2024 से शुरू होगी। इससे ग्राहकों को त्योहारों पर अपनी नई सिट्रोएन सी3 एयरक्रॉस एसयूवी खरीदना और आसान हो जाएगा।

टाटा मोटर्स ने एसयूवी एक्सिलेंस में नए दौर की शुरुआत की

हैरियर और सफारी के लिए 25 हजार रुपये में बुकिंग खोलने की घोषणा की

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने बहुप्रतीक्षित नई हैरियर और सफारी मॉडलों के लिए बुकिंग खोलने की घोषणा की। टाटा मोटर्स की इससे पहले लॉन्च की गई दूसरी गाड़ियों की असाधारण सफलता के बाद नई हैरियर और सफारी आधुनिक तकनीक, बेमिसाल सेफ्टी फीचर्स और शानदार डिजाइनिंग से कार ड्राइविंग के अनुभव को फिर से पारिभाषित करने के लिए तैयार हैं। यह नवाचार एवं उत्कृष्टता के प्रति टाटा मोटर्स के समर्पण की मिसाल है। टाटा की इन दोनों नई गाड़ियों के लिए बुकिंग आज से खोल दी गई हैं। उपभोक्ता टाटा मोटर्स की डीलरशिप या कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इन दोनों एसयूवी में से अपनी पसंद की गाड़ी की बुकिंग केवल 25,000 रुपये में करा सकते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक श्री शैलेश चंद्रा ने इस अवसर पर कहा, 'हम नई हैरियर और सफारी के लिए आज से बुकिंग शुरू कर काफी उत्साहित हैं। एक्सिलेंस के प्रति हमारे समर्पण और उपभोक्ताओं के बेशकीमती फीडबैक ने इन शानदार गाड़ियों के लिए नए जमाने में अपनी खास जगह बनाने के युग का सूत्रपात किया है। सक्षम ओमेगार्क पर निर्मित इन दोनों एसयूवी में टाटा मोटर्स की शानदार डिजाइन, एडवांस्ड फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर और मजबूत पावर ट्रेन की सर्वश्रेष्ठ विरासत को कायम रखा गया है और इन्हें हर मोर्चे पर बेहतर बनाने की दोबारा परिकल्पना की गई। हम टाटा मोटर्स की एसयूवी की नई लहर आपके सामने पेश कर काफी उत्साहित हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये दोनों प्रॉडक्ट्स न केवल उपभोक्ताओं, बल्कि हमारे ब्रैंड की भी क्षमता और महत्वांकांक्षों का प्रतिनिधित्व करेंगे!' नई हैरियर और सफारी को बेहतर ढंग से पारिभाषित पर्सोना की रणनीति के तहत बनाया गया है। यह इस श्रेणी में उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर शानदार फीचर्स और सुविधाएं प्रदान करने वाली एसयूवी है। टाटा मोटर्स की पहले लॉन्च हुई कारों की विरासत कायम रखते हुए इन कारों के निर्माण में हर उपभोक्ता वर्ग की जरूरत को पूरा करने की दोबारा परिकल्पना की गई है।

आईएमएफ ने बढ़ाया भारत के ग्रोथ का पूर्वानुमान

नई दिल्ली । एजेंसी

इंटरनैशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने मौजूदा फाइनेंशल ईयर के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को 0.2 प्रतिशत बढ़ाकर 6.3इ बढ़ा दिया है। उसका कहना है कि जून तिमाही के दौरान खपत में काफी तेजी देखने को मिली है। दूसरी ओर उसने चीन के ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। IMF ने जुलाई में भारत की \RGDP ग्रोथ रेट के 6.1% रहने का अनुमान जताया था। यह आंकड़ा इस अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक के 6.5 प्रतिशत के अनुमान से कम था। घ्इ ने कहा कि मॉनिटरी पॉलिसी अनुमानों के मुताबिक मध्यम अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक इंफ्लेशन के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। IMF ने कहा कि भारत ने अप्रैल-जून, 2023 के दौरान 35 से 40 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात रूस से किया, जबकि यूक्रेन युद्ध से पहले यह आंकड़ा पांच प्रतिशत से भी कम था। IMF के मुताबिक भारत में अप्रैल-जून तिमाही में खपत के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। इस तिमाही में देश की जीडीपी 7.8 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी। एक सरकारी सर्वेक्षण में यह तथ्य निकल कर आया है कि देश में जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की बेरोजगारी दर छह साल के निचले स्तर, 3.2 प्रतिशत पर रही। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रमबल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। National Sample Survey Office (NSSO) की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर (UR) 2021-22 में 4.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.2 प्रतिशत हो गई।

आईएचसीएल ने एचएचएच फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नए स्किल सेंटर्स केंद्रों की योजना बनाई है

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी, इंडियन होटल्स कंपनी (आईएचसीएल) ने आज हेड हेल्ड हाई (एचएचएच) के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की, जो पूरे भारत में ग्रामीण समुदायों में युवा परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली भारत की अग्रणी गैर-लाभकारी संस्था है। इस अवसर पर गौरव पोखरियाल, एग्जीक्यूटिव वाईस प्रेसिडेंट – ह्यूमन रिसोर्सेज आईएचसीएल ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग सामाजिक प्रगति और समावेशी विकास के लिए आईएचसीएल की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, और हमारे पाथ्या के ईएसजी ट्र फ्रेमवर्क के अनुरूप है। आईएचसीएल हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न उद्योगों में रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए देश भर में चुनिंदा स्थानों पर स्किल्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल सेंटर्स सशक्तिकरण के केंद्र के रूप में काम करेंगे, आवश्यक स्किल डेवेलपमेंट को बढ़ावा देंगे जो रूरल यूथ और प्रोफेशनल वर्ल्ड के बीच की खाई को पाटेंगे। वे अनुरूप प्रशिक्षण मॉड्यूल पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आज के कॉम्पिटिशन जॉब मार्किट की मांगों के अनुरूप हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए, हेड हेल्ड हाई फाउंडेशन के सीईओ पंकज सिंह ठाकुर ने कहा, 'यह एसोसिएशन ग्रामीण युवाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करेगा, उन्हें अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने और पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अवसरों का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाएगा। इस पहल के लिए आईएचसीएल के साथ साझेदारी करके हमें खुशी हो रही है।'' हेड हेल्ड हाई के सभी रूपों में असमानता को कम करने के प्रयासों में जरूरतों का मूल्यांकन, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, ग्रामीण उद्यमिता, वित्तीय समावेशन, स्किल-आधारित प्रशिक्षण, लाइवलीहुड सपोर्ट, कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग और बहुत कुछ शामिल हैं।

इंडियन हॉस्पिटैलिटी के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित, एचसीएल अपने पाथ्य फ्रेमवर्क के तहत उद्योग के समग्र विकास में योगदान करते हुए योग्य युवाओं और उनके परिवारों को विकसित करने और समर्थन करने के उद्देश्य से उद्योग-प्रासंगिक प्रतिभा पूल के निर्माण में निवेश करना जारी रखता है।

नोएडा-ग्रेनो बना डिफेंस, एयरोस्पेस और सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री की पहली पसंद

नई दिल्ली। एजेंसी

नोएडा और ग्रेनो अथॉरिटी में इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन के लिए बनाई जा रही नई पॉलिसी फाइनल हो गई है। पॉलिसी में दोनों अथॉरिटी एरिया में लगने वाले उद्योगों की सूची में 40 और नई इंडस्ट्री शामिल की गई हैं। इनमें डिफेंस, एयरोस्पेस और सेमी कंडक्टर मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्री अहम हैं। अब इन उद्योगों से जुड़े ग्रुप भी सीधे नोएडा और ग्रेनो अथॉरिटी में प्लॉट के लिए आवेदन कर अपनी यूनिट लगाएंगे। पॉलिसी में बड़ा बदलाव यह भी हुआ है कि ई-नीलामी हटाए जाने के साथ 4 हजार वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के प्लॉट के आवंटन को लागू ड्रॉ की प्रक्रिया भी हटा दी गई है। अब सभी प्लॉट का आवंटन इंटरव्यू और अन्य मानक के आधार पर होंगे। यह मानक तय करने और पॉलिसी बनाने को लेकर शनिवार को ऑनलाइन बैठक औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई थी।

गौरतलब है कि पहले जिले की तीनों अथॉरिटी में औद्योगिक प्लॉट का आवंटन ई-नीलामी से हो रहा था। औद्योगिक विकास आयुक्त ने पत्र जारी कर ई-नीलामी को हटा दिया था। इसके बाद नई पॉलिसी बननी थी। तय हुआ था कि इस नई पॉलिसी में इंटरव्यू समेत आवेदन के अन्य मानक रखे जाएंगे। फिर नोएडा, ग्रेनो अथॉरिटी ने इसका ड्राफ्ट बनवाया। साथ ही, शासन स्तर पर भी वर्कआउट करवाया गया। इसमें प्लॉट आवंटन के 100 नंबर रखे गए। बाकी कंपनी की मौजूदा स्थिति, निवेश, कैश फ्लो, रोजगार के मौके, देनदारी, फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (एफडीआई) समेत अन्य मानक रखे गए हैं। अब यह मानक भी तय हो गए और कौन से मानक पर कितने नंबर दिए जाने हैं यह भी तय हो गया है। कंपनी का अगर फॉर्च्यून या फोर्ब्स की सूची में शामिल है तो उसे आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले आवंटन ड्रॉ और इंटरव्यू से होता था, लेकिन फिर पारदर्शिता के दावे के साथ अप्रैल-2022 के बाद से तीनों अथॉरिटी में इंडस्ट्रियल प्लॉट के आवंटन में ई-नीलामी की व्यवस्था शुरू की गई थी। नोएडा, ग्रेनो और यमुना अथॉरिटी में 04, 05 और 26 अप्रैल 2022 की बोर्ड बैठकों में प्लॉट ई-नीलामी के जरिए आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। व्यवस्था यह लागू हुई थी कि 4 हजार वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के प्लॉट का आवंटन ड्रॉ और बाकी का आवंटन ई-नीलामी से होगा। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी में 3 स्कीम लॉन्च कर प्लॉट आवंटन हुआ। इसी तरह ग्रेनो और यमुना में भी कई बार ई-नीलामी हुई थीं। ई-नीलामी में अथॉरिटी का फायदा हो रहा था। लेकिन कई उद्यमी संगठन इसके पक्ष में नहीं थे।

सनराइज सेक्टर का नया कांसेप्ट

इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन पॉलिसी में नोएडा-ग्रेनो के लिए सनराइज सेक्टर का नया कांसेप्ट आया है। इसका मकसद एक ही तरह की इंडस्ट्रियों को एक जगह पर स्थापित करवाकर क्लस्टर डिवेलपमेंट पर जोर देना है। सनराइज सेक्टर सूचना प्रौद्योगिकी को कहा जाता है इसे अंग्रेजी में आईटी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इस कांसेप्ट से आईटी सेक्टर को सहूलियत के साथ विशेष आमंत्रण नोएडा-ग्रेनो में मिलेगा। वहीं सूची में अब तक 142 इंडस्ट्री नोएडा में शामिल थीं। इनको बढ़ाकर 182 कर दिया गया है।

नोएडा-ग्रेनो अथॉरिटी जल्द लॉन्च करेंगी अपनी स्कीम

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, फाइनल हुई पॉलिसी पर शासन स्तर से नोएडा-ग्रेनो अथॉरिटी को निर्देश मिल गए हैं। निर्देश यह है कि इस पॉलिसी के आधार पर प्लॉट आवंटन की स्कीम लॉन्च करने के ब्रोशर तैयार किए जाएं। इसके बाद दोनों अथॉरिटी ने तैयारी शुरू कर दी है। नोएडा अथॉरिटी करीब 12 प्लॉट तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 30-35 इंडस्ट्रियल प्लॉट की स्कीम लाने की तैयारी में है। नोएडा में एक सड़क की वजह से 8 इंडस्ट्रियल प्लॉट की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। सेक्टर-164 में अगर यह सड़क बन जाती है तो अथॉरिटी 20 प्लॉट स्कीम में शामिल कर सकती है। यह सभी प्लॉट बड़े क्षेत्रफल वाले हैं।

ADIA ने रिलायंस रिटेल में किया बड़ा निवेश, 4966.80 करोड़ रुपये में खरीदी 0.59 प्रतिशत हिस्सेदारी

नयी दिल्ली। एजेंसी

अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 0.59 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 4,966.80 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आरआईएल ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि इस निवेश के तहत रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) का इक्विटी मूल्य 8.381 लाख करोड़ रुपये (100.83 अरब अमेरिकी डॉलर) है। इस तरह यह इक्विटी मूल्य के हिसाब से देश की शीर्ष चार कंपनियों में शामिल है। कंपनी ने बताया कि एडीआईए की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के जरिये होने वाले इस निवेश से एआईडीए को पूर्ण चुकता आधार पर आरआरवीएल में 0.59 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी मिलेगी। आरआरवीएल, आरआईएल के खुदरा कारोबार की मूल कंपनी है। यह किराना, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और लाइफस्टाइल तथा फार्मा जैसी श्रेणियों में 18,500 से अधिक स्टोर और डिजिटल कॉमर्स मंचों का संचालन करती है। आरआरवीएल की कार्यकारी निदेशक ईशा मुकेश अंबानी ने कहा कि आरआरवीएल में एक निवेशक के रूप में एडीआईए के लगातार समर्थन तथा उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर हम खुश हैं। विश्व स्तर पर मूल्य निर्माण के उनके लंबे अनुभव से हमें फायदा होगा और भारतीय खुदरा क्षेत्र में बदलाव को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आरआरवीएल में एडीआईए का निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार के बुनियादी सिद्धांतों में उनके भरोसे को दर्शाता है। एडीआईए के निजी इक्विटी विभाग के कार्यकारी निदेशक हमद शाहवान अलदाहेरी ने कहा कि रिलायंस रिटेल ने अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहे बाजार में मजबूत वृद्धि और अनुकूलन का प्रदर्शन किया है। यह निवेश अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों का समर्थन करने की हमारी रणनीति के अनुरूप है।

कोस्टा कॉफी ने जारी रखा सफलता का सफर

नई दिल्ली में अपने 150वें स्टोर के शुभारंभ का जश्न मनाया

इंदौर। भारत में कमर्शियल बेवरेज कैटेगरीज़ में कोका-कोला का अग्रणी कॉफी ब्राण्ड कोस्टा कॉफी ने नई दिल्ली के राजौरी गार्डन में अपने स्टोर के शुभारंभ की घोषणा की है। भारत में यह इसका 150वां स्टोर है। यह उपलब्धि अपनी उपस्थिति बढ़ाने और देशभर में कॉफी के प्रेमियों को बेजोड़ अनुभव देने के लिये कोस्टा कॉफी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

कोस्टा कॉफी ने 2005 में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपने कैफे का शुभारंभ कर भारतीय बाजार में कदम रखा था और भारत में अपना सफर शुरू किया था। पिछले साल देवयानी इंटरनेशनल के साथ गठजोड़ में कोस्टा कॉफी ने भारत में अपने विस्तार की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की और लगभग 60 स्टोर जोड़े। इस गति को बनाये रखते हुए, कोस्टा कॉफी देशभर के मौजूदा बाजारों और नये शहरों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। इसका मौजूदा लक्ष्य भारत के शीर्ष 8 से 10 शहरों में नये स्टोर खोलना है। कोस्टा कॉफी ने एयरपोर्ट्स, हाइवेज और हेल्थकेयर जैसे खास चैनलों में जाने की प्राथमिकता तय की है।

भारत का कॉफी उद्योग दिलचस्प तरीके से स्पेशियल्टी कॉफी और प्रीमियमाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, खासकर शहरी युवाओं के लिये, जिन्होंने कॉफी की दुकानों को जीवंत सामुदायिक केन्द्रों में बदल दिया है। यह बदलाव चाय वाली संस्कृति के लिये मशहूर देश में खासतौर से रोचक है। कोस्टा कॉफी इस क्रांति में सबसे आगे है, यह उपभोक्ताओं की बदलती पसंद के अनुसार बढ़ रहा है और कॉफी की अद्भुत संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है।

कोस्टा कॉफी का 150वां कोस्टा कॉफी स्टोर हाथ से बनी और स्थानीय आधार पर प्राप्त की जाने वाली कॉफी पिलाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। कोस्टा कॉफी की कलात्मक और अभिनव डिजाइन लैंग्वेज के अनुसार तैयार किये गये इस स्टोर का लक्ष्य कॉफी प्रेमियों को आरामदायक और जीवंत जगह देना है, जहाँ वे अपने पसंदीदा ब्रूज़ का मजा ले सकें।

मध्य भारत के सबसे बड़ा टी.जी.एल गरबा लाभ गंगा में 19 अक्टूबर से प्रांरभ

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर जो कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और सभी त्योहारों को मनाने में पूरे भारत में प्रसिद्ध है इसी को देखते हुए तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड कम्पनी ने इंदौर वासियों के लिए मध्य भारत का सबसे बड़ा व अनूठे गरबे का प्रयोजन किया है जिसमें की शहर के वरिष्ठ लोगों के अलावा मुम्बई की फिल्म इंडस्ट्री से भी कई नामी गिरामी हस्तियां भी शिरकत करेंगी। मध्य भारत का सबसे भव्य एवं विशाल गरबा जो 19 से 22 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें भारत के प्रसिद्ध कलाकार सम्मिलित होने जा रहे है जिसमें अली असगर, दिलिप जोशी (तारक मेहता फेम) एवं मुनमुन दत्ता (तारक मेहता फेम) प्रमुख है जो गरबे में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड द्वारा आयोजित इस विशाल नवरात्री पर्व में पूरे भारत से लोग आकर गरबे का आनंद लेंगे, इस गरबे के टिकिट अब बुक माय शो पर उपलबंध हो चुके है जिससे इस विशाल आयोजन में आम जनता आसानी से पहुंच सकें। इस गुजराती गरबे की शोभा बढ़ाने के लिए इसमें 19 को अघोरी म्यूजिक, 20 को जोली राठौर, 21 को भाई-भाईं फेम अरविंद वेगड़ा एवं 22 अक्टूबर को मेरी मज़ी फेम देवांग पटेल पधार रहे है, इंदौर की जनता काफी समय से इस विशाल गरबे का इंतेजार कर रही थी क्योंकि आज तक मध्य भारत में इतने विशाल एवं भव्य स्तर पर कभी कोई गरबा नहीं हुआ है, जिसके तहत सुरक्षा की भारी व्यवस्था की गई है ताकि इंदौरवासी इस गरबे का आनंद ले सकें । ज्ञात हो कि शहर में इस तरह का अनूठा गरबा पहली बार हो रहा है इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी लोकप्रियता को देखते हुए, बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां इसमें शामिल हो रही है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।